VAJIRAO & REDDY INSTITUTE
India's Top Potential Training Institute for IAS
+918988885050
+918988886060
www.vajiraoinstitute.com
info@vajiraoinstitute.com

TODAY'S ANALYSIS
(आज का विश्लेषण)
(06 March 2025)

Sources:

The Hindu, The Indian Express, The Economics Times & PIB

Important News:

- अमेरिका के 'पारस्परिक टैरिफ' योजना का भारत पर पड़ने वाला संभावित परिणाम
- मिस्र की 'गाजा पुनर्निर्माण योजना' और इस पर इजरायल और अमेरिका की प्रतिक्रिया
- सोनप्रयाग-केदारनाथ, गोविंदघाट-हेमकुंड साहिब जी रोपवे परियोजनाएं
- MCQ

ADDRESS:
19/1A Shakti Nagar, Nagiya Park Near Delhi University, New Delhi - 110007 (India)

अमेरिका के 'पारस्परिक टैरिफ' योजना का भारत पर पड़ने वाला संभावित परिणाम:

चर्चा में क्यों है?

- अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 4 मार्च को एक बार फिर भारत पर उसके ऊंचे टैरिफ को लेकर निशाना साधा। उन्होंने संकेत दिया कि व्यापार समझौते के लिए बातचीत से भारत को पारस्परिक टैरिफ जैसे व्यापक शुल्कों पर रियायतें नहीं मिल सकती हैं, जो 2 अप्रैल से प्रभावी होने वाले हैं। उन्होंने ऑटो सेक्टर का विशेष उल्लेख किया, जहां उन्होंने कहा कि भारत 100 प्रतिशत से अधिक टैरिफ लगाता है।

- इस संदर्भ में राष्ट्रपति ट्रंप ने अमेरिकी कांग्रेस के संयुक्त सत्र को संबोधित करते हुए कहा "भारत हमसे 100 प्रतिशत टैरिफ लगाता है; यह व्यवस्था अमेरिका के लिए उचित नहीं है, कभी नहीं थी"।

- उल्लेखनीय है कि यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका यात्रा के कुछ ही हफ्तों बाद आया है, जिसने भारतीय उद्योग जगत में उम्मीद जगाई थी कि अमेरिका के साथ व्यापार समझौता भारत में अमेरिकी उत्पादों के लिए बाजार पहुंच के बदले भारत को व्यापक टैरिफ से राहत दिलाने में मदद कर सकता है।

भारत पर अमेरिका के 'पारस्परिक शुल्क' का क्या प्रभाव पड़ सकता है?

- रेटिंग एजेंसी मूडीज ने पिछले महीने कहा था कि भारत, वियतनाम और थाईलैंड जैसे विकासशील देशों में अमेरिका के सापेक्ष दरों में सबसे अधिक अंतर है और अमेरिका के पारस्परिक शुल्कों से इन पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ सकता है।
- मूडीज की रिपोर्ट में कहा गया है कि "भारत का क्षेत्र के अधिकांश अन्य देशों के सापेक्ष समग्र जोखिम कम है, हालांकि खाद्य और वस्त्र जैसे कुछ क्षेत्रों के साथ-साथ दवा उत्पादों को भी जोखिम का सामना करना पड़ सकता है"।
- मूडीज ने बताया कि ऐसा कहा जाता है कि, इनमें से अधिकांश अर्थव्यवस्थाओं के पास पर्याप्त मैक्रोप्रूडेंशियल बफर और ठोस मौद्रिक नीति ढांचे हैं जो बाहरी झटकों के प्रभाव को कम करेंगे। इसके अलावा, क्षेत्र के अधिकांश भागों में घरेलू मांग मजबूत बनी हुई है, जिसे वैश्विक और क्षेत्रीय वित्तीय स्थितियों में मामूली सुधार से बल मिला है।

'पारस्परिक शुल्क' के संभावित नकारात्मक प्रभावित क्षेत्र:

कृषि क्षेत्र को नुकसान की संभावना:

- भारत के लिए कृषि सबसे अधिक असुरक्षित है, क्योंकि दोनों देशों के बीच टैरिफ में बहुत अंतर है। कृषि व्यापार भी संवेदनशील है, किसान यूनियनें कानूनी रूप से गारंटीकृत MSP की मांग को लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन कर रही हैं।
- पिछले महीने जारी भारतीय अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंध अनुसंधान परिषद की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत 17% की साधारण औसत दर से टैरिफ लगाता है, जबकि अमेरिका 3.3% टैरिफ लगाता है।

ऑटो, फार्मा को नुकसान की संभावना:

- ऑटोमोबाइल और फार्मास्युटिकल सेक्टर पर भी ऐसे समय में असर पड़ने की उम्मीद है। दोनों उद्योग भारत के सबसे सफल उद्योगों में से हैं, जिनमें पर्याप्त मूल्य-संवर्धन और निर्यात शक्ति है, खासकर यूरोप और अमेरिका को।
- ऑटोमोबाइल सेक्टर में टैरिफ अंतर 23.1% है; रसायन और फार्मास्यूटिकल्स के लिए, 8% है। 2023 में भारत द्वारा अमेरिका को निर्यात किए जाने वाले 20 अरब डॉलर के अंतिम उपभोक्ता सामानों में फार्मा उत्पादों का हिस्सा 21.9% था।

भारत-अमेरिका द्विपक्षीय व्यापार समझौता के लिए अनिश्चितता:

- उल्लेखनीय है कि भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय व्यापार समझौता (BTA) पर काम चल रहा है, और भारतीय अधिकारियों को उम्मीद है कि वे व्यापक टैरिफ जैसे कि पहले घोषित स्टील और एल्युमीनियम पर 25% शुल्क और आगामी पारस्परिक टैरिफ पर रियायतें प्राप्त करेंगे।
- वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल वर्तमान में संयुक्त राज्य अमेरिका के व्यापार प्रतिनिधि (USTR) जैमीसन ग्रीर से मिलने के लिए अमेरिका में हैं, जिन्हें ट्रम्प प्रशासन की टैरिफ योजना को लागू करने का काम सौंपा गया है।
- हालांकि व्यापार विशेषज्ञों ने उल्लेख किया है कि कनाडा और मैक्सिको पर 25% टैरिफ, विश्व व्यापार संगठन (WTO) के मानदंडों के अनुरूप व्यापार सौदों के लिए ट्रंप प्रशासन की उपेक्षा को दर्शाता है, और भारत के साथ किसी भी भविष्य के व्यापार समझौते के लिए अमेरिकी पालन पर सवालिया निशान लगाता है।

अमेरिका की व्यापार नीति में WTO पर सवाल उठाए गए:

- अमेरिका के टैरिफ, जो विश्व व्यापार संगठन (WTO) के कई सिद्धांतों की अवहेलना करते हैं और भारत को भविष्य की अनिश्चितता के लिए उजागर करते हैं, नई अमेरिकी 2025 व्यापार नीति के साथ मेल खाते हैं, जो इस बात पर जोर देती है

कि WTO ने "अपना रास्ता खो दिया है" और इसमें सुधार की आवश्यकता है। नया व्यापार दस्तावेज WTO के 'विशेष और विभेदक उपचार (SDT)' प्रावधानों के तहत भारत जैसे विकासशील देशों द्वारा मांगी गई रियायतों और छूटों की भी आलोचना करता है।

- 3 मार्च को जारी की गई अमेरिकी 2025 व्यापार नीति में कहा गया है, "SDT का दर्जा कई लाभ प्रदान करता है, जिसमें उदार संक्रमण अवधि, उच्च टैरिफ बंधन और निषिद्ध सब्सिडी का उपयोग करने की क्षमता शामिल है। मौजूदा प्रणाली के तहत, देश केवल 'विकासशील' के रूप में स्व-घोषणा करके SDT लाभ प्राप्त कर सकते हैं - चाहे उनकी प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय या विश्व बैंक के अनुसार उनकी आय वर्गीकरण कुछ भी हो"।

WTO द्वारा चीन की आर्थिक प्रणाली को संबोधित नहीं किया:

- नए अमेरिकी व्यापार नीति दस्तावेज़ में तर्क दिया गया है कि, इसकी स्थापना के समय, WTO का उद्देश्य और दिशा स्पष्ट थी, जिसमें पक्ष “खुले, बाजार-उन्मुख नीतियों के आधार पर विश्व व्यापार प्रणाली में भाग लेने” के लिए अपना दृढ़ संकल्प व्यक्त करते थे। हालांकि, 30 साल बाद, WTO की “व्यवहार्यता और स्थायित्व” पर लगातार सवाल उठ रहे हैं।

+918988885050
+918988886060
www.vajiraoinstitute.com
info@vajiraoinstitute.com

- अमेरिकी व्यापार नीति के अनुसार जब चीन ने बाजार-उन्मुख सुधार पथ को छोड़ दिया, जिस पर उसका 2001 में प्रवेश आधारित था और राज्य-नेतृत्व वाली, गैर-बाजार आर्थिक प्रथाओं को अपनाया, तो WTO चीन की आर्थिक प्रणाली को संबोधित करने में न तो सक्षम था और न ही इच्छुक था, जो WTO सदस्यों द्वारा परिकल्पित खुले, बाजार-उन्मुख दिशा के साथ मौलिक रूप से असंगत है और WTO और उसके समझौतों के मूल सिद्धांतों के विपरीत है।

मिस्र की 'गाजा पुनर्निर्माण योजना' और इस पर इजरायल और अमेरिका की प्रतिक्रिया:

चर्चा में क्यों है?

- अरब लीग ने 4 मार्च को मिस्र द्वारा दिए गए अगले पांच वर्षों में 'गाजा के पुनर्निर्माण' के प्रस्ताव का स्वागत किया। लीग के महासचिव अहमद अबुल घीत ने कहा, "मिस्र की योजना अब एक अरब देशों की योजना है"।
- उल्लेखनीय है कि काहिरा में आयोजित शिखर सम्मेलन में अरब नेताओं ने इस 53 अरब डॉलर की योजना में इजरायल और फिलिस्तीन के लिए दो-राज्य समाधान के लिए लीग की प्रतिबद्धता पर जोर दिया गया। साथ ही फिलिस्तीनी लोगों के अधिकारों पर भी जोर दिया गया है और आबादी को विस्थापित करने की किसी भी संभावना को खारिज कर दिया गया है।

- इस शिखर सम्मेलन के निष्कर्षों का हमास ने स्वागत किया, इजरायल ने इसे अस्वीकार कर दिया और ट्रंप प्रशासन ने इस पर ठंडी प्रतिक्रिया दी।

राष्ट्रपति ट्रंप की गाज़ा को लेकर क्या योजना है?

- राष्ट्रपति ट्रम्प ने प्रस्ताव रखा है कि अमेरिका गाजा पट्टी पर कब्जा कर लेगा और इस क्षेत्र से बम और मलबे को हटा देगा। इस प्रक्रिया में, अमेरिका गाज़ा में समुद्र के सामने की संपत्ति बनाएगा जो "मध्य पूर्व का रिवेरा" बन जाएगा, जिससे "दुनिया के लोगों" को वहां आने का निमंत्रण मिलेगा।
- राष्ट्रपति ट्रम्प ने गाजा से लगभग 20 लाख गाज़ा वासियों को पड़ोसी देश जॉर्डन और मिस्र में स्थानांतरित करने के विचार पर भी जोर दिया, एक प्रस्ताव जिसे दोनों देशों और अन्य अरब देशों ने सख्ती से खारिज कर दिया।

मिस्र की 'गाजा पुनर्निर्माण की योजना' क्या कहती है?

- मिस्र की 'गाजा पुनर्निर्माण की योजना' में दो चरण हैं: रिकवरी चरण और पुनर्निर्माण चरण।

रिकवरी चरण:

- रिकवरी चरण, छह महीने तक चलने की उम्मीद है और इसकी लागत 2 अरब डॉलर है। इसमें 50 मिलियन टन से अधिक मलबे को साफ करने, लैंडलाइन और

अप्रयुक्त बम सामग्री को हटाने और अस्थायी आवास प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।

- इस दौरान 15 लाख से अधिक विस्थापित लोगों को समायोजित करने के लिए अस्थायी आवास आश्रयों के लिए सात निर्दिष्ट स्थलों का प्रस्ताव दिया गया है।

पुनर्निर्माण चरण:

- पुनर्निर्माण चरण, साढ़े चार वर्षों में दो चरणों में पूरा किया जाएगा।
- इस चरण का पहला चरण 20 अरब डॉलर बजट पर 2027 तक चलेगा और सड़कों और सार्वजनिक उपयोगिताओं जैसे आवश्यक बुनियादी ढांचे के पुनर्निर्माण पर ध्यान केंद्रित करेगा। इसका लक्ष्य 16 लाख लोगों के लिए 200,000 स्थायी आवास इकाइयों का निर्माण और 20,000 एकड़ भूमि का पुनर्ग्रहण करना भी है।
- दूसरा चरण 2030 तक चलेगा और इसका अनुमानित बजट 30 अरब डॉलर होगा, तथा इसमें 200,000 आवासीय इकाइयां बनाई जाएंगी। इसमें एक वाणिज्यिक बंदरगाह, एक प्रौद्योगिकी केंद्र, औद्योगिक क्षेत्र, समुद्र तट होटल और एक हवाई अड्डे की योजना भी शामिल है।

गाजा में मामलों का प्रबंधन का प्रभारी कौन होगा?

- इस योजना में गाजा में मामलों का प्रबंधन करने के लिए "स्वतंत्र फिलिस्तीनी टेक्नोक्रेट" के एक समूह की बात कही गई है, जो वास्तव में हमास की जगह लेगा। टेक्नोक्रेटिक सरकार मानवीय सहायता की देखरेख के लिए जिम्मेदार होगी और गाजा को प्रशासित करने के लिए फिलिस्तीनी प्राधिकरण के लिए मार्ग प्रशस्त करेगी।
- सुरक्षा के मोर्चे पर, मिस्र और जॉर्डन दोनों ने फिलिस्तीनी पुलिस अधिकारियों को प्रशिक्षित करने और उन्हें गाजा में तैनात करने का वचन दिया है। पुनर्निर्माण पूरा होने तक गाजा में शासन की देखरेख के लिए एक शांति मिशन को अधिकृत करने पर विचार करने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से भी आह्वान किया है।

इजराइल द्वारा मिस्र की योजना को खारिज किया गया:

- इजराइल ने राष्ट्रपति ट्रंप के प्रस्ताव के लिए अपने समर्थन की पुष्टि की, जिसमें फिलिस्तीनियों को जॉर्डन और मिस्र में स्थानांतरित करने की बात कही गई है।
- इजराइल ने फिलिस्तीनी प्राधिकरण और फिलिस्तीन शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र राहत और कार्य एजेंसी (UNRWA) पर अरब लीग शिखर सम्मेलन की निर्भरता की आलोचना की, उन पर भ्रष्टाचार और आतंकवाद से संबंधों का आरोप लगाया।

- इसके अतिरिक्त, इजराइल ने काहिरा शिखर सम्मेलन के अंतिम वक्तव्य की निंदा करते हुए तर्क दिया कि यह वक्तव्य "7 अक्टूबर के बाद जमीनी हकीकत" को ध्यान में रखने में विफल रहा।

पुनर्निर्माण योजना पर अमेरिकी प्रतिक्रिया:

- ट्रम्प प्रशासन ने अरब लीग समर्थित गाजा पुनर्निर्माण योजना को खारिज कर दिया है, जिसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति अपने स्वयं के दृष्टिकोण पर कायम हैं, जिसमें क्षेत्र के फिलिस्तीनी निवासियों को निष्कासित करना और इसे संयुक्त राज्य अमेरिका के स्वामित्व वाले "रिवेरा" में बदलना शामिल है।

सोनप्रयाग-केदारनाथ, गोविंदघाट-हेमकुंड साहिब जी रोपवे परियोजनाएं:

चर्चा में क्यों है?

- केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 5 मार्च को पर्वतमाला परियोजना के तहत सोनप्रयाग और केदारनाथ तथा गोविंदघाट और हेमकुंड साहिब जी के बीच रोपवे परियोजनाओं को मंजूरी दी। 12.9 किलोमीटर और 12.4 किलोमीटर रोपवे को क्रमशः 4,081.28 करोड़ रुपये और 2,730.13 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई है।

- दोनों परियोजनाओं से निर्माण और संचालन के चरणों के साथ-साथ आतिथ्य, यात्रा, खाद्य और पेय पदार्थ, और पूरे वर्ष पर्यटन जैसे संबंधित पर्यटन क्षेत्रों में पर्याप्त रोजगार के अवसर पैदा होने की उम्मीद है।
- उल्लेखनीय है कि इस वर्ष की शुरुआत में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा था कि पर्वतमाला परियोजना या राष्ट्रीय रोपवे विकास कार्यक्रम के तहत सरकार ने 1.25 लाख करोड़ रुपये की परियोजनाओं की पहचान की है।

सोनप्रयाग-केदारनाथ रोपवे परियोजना:

- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 5 मार्च को केदारनाथ रोपवे परियोजना को मंजूरी दी। कुल 12.9 किलोमीटर लंबे इस रोपवे पर करीब 4,081 करोड़ रुपये का खर्च आएगा।
- यह रोपवे परियोजना सोनप्रयाग से केदारनाथ तक होगी। इस परियोजना डिजाइन, निर्माण, वित्त, संचालन और हस्तांतरण (DBFOT) मोड पर विकसित किया जाएगा।
- रोपवे को सार्वजनिक-निजी भागीदारी में विकसित करने की योजना है और यह सबसे उन्नत ट्राई-केबल डिटैचेबल गोंडोला (3S) तकनीक पर आधारित होगा, जिसकी डिजाइन क्षमता प्रति घंटे 1,800 यात्रियों की है और यह प्रतिदिन 18,000 यात्रियों को ले जा सकेगा।

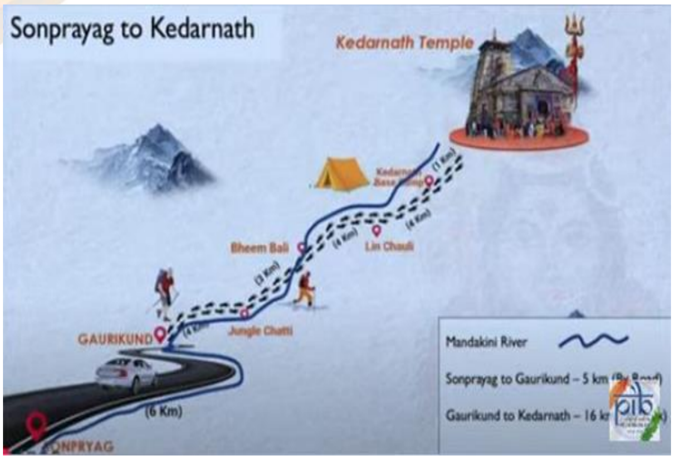

- इस परियोजना से केदारनाथ आने वाले तीर्थयात्रियों को पर्यावरण के अनुकूल, आरामदायक और त्वरित यात्रा विकल्प प्रदान करके बहुत लाभ होने की उम्मीद है, जिससे यात्रा का समय एक दिशा में लगभग 8 से 9 घंटे से घटकर केवल 36 मिनट रह जाएगा।

+918988885050
+918988886060
www.vajiraoinstitute.com
info@vajiraoinstitute.com

- उल्लेखनीय है कि केदारनाथ मंदिर की वर्तमान यात्रा में गौरीकुंड से 16 किमी की चुनौतीपूर्ण चढ़ाई शामिल है, और प्रस्तावित रोपवे का उद्देश्य तीर्थयात्रियों के लिए एक सुविधाजनक विकल्प प्रदान करना और सोनप्रयाग और केदारनाथ के बीच हर मौसम में संपर्क सुनिश्चित करना है।
- **केदारनाथ मंदिर:**
  - 12 पवित्र ज्योतिर्लिंगों में से एक केदारनाथ उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में 3,583 मीटर की ऊँचाई पर स्थित है।
  - यह मंदिर हर साल अक्षय तृतीया से दिवाली तक लगभग 6 से 7 महीने तक सुलभ रहता है, इस अवधि के दौरान लगभग 20 लाख तीर्थयात्री आते हैं।

गोविंदघाट-हेमकुंड साहिब जी रोपवे परियोजना:

- CCEA ने 'डिजाइन, निर्माण, वित्त, संचालन और हस्तांतरण (DBFOT)' मॉडल के तहत इस परियोजना को भी मंजूरी दी। इस रोपवे परियोजना को सार्वजनिक-निजी भागीदारी के माध्यम से विकसित किया जाएगा। 12.4 किलोमीटर लम्बी इस परियोजना का विकास कुल 2,730.13 करोड़ रुपये की पूंजीगत लागत से किया जाएगा।

- यह गोविंदघाट और हेमकुंड साहिब जी के बीच सभी मौसम में अंतिम मील की कनेक्टिविटी प्रदान करेगा। प्रस्तावित रोपवे का उद्देश्य हेमकुंड साहिब जी आने वाले तीर्थयात्रियों और फूलों की घाटी जाने वाले पर्यटकों को सुविधा प्रदान करना है। हेमकुंड साहिब जी की वर्तमान यात्रा में गोविंदघाट से 21 किलोमीटर की चुनौतीपूर्ण चढ़ाई शामिल है।

- **हेमकुंड साहिब जी:**
  - ➢ हेमकुंड साहिब जी उत्तराखंड के चमोली जिले में 15,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित एक पूजनीय तीर्थ स्थल है।
  - ➢ इस स्थल पर स्थित गुरुद्वारा मई से सितंबर तक सालाना लगभग पांच महीने के लिए खुला रहता है, जिसमें हर साल 1.5 से 2 लाख तीर्थयात्री आते हैं।
  - ➢ हेमकुंड साहिब जी की यात्रा फूलों की घाटी के प्रवेश द्वार के रूप में भी काम करती है, जो गढ़वाल हिमालय में स्थित यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है।

+918988885050
+918988886060
www.vajiraoinstitute.com
info@vajiraoinstitute.com

MCQ

Q.1. चर्चा में रहे अमेरिका की 'पारस्परिक टैरिफ' योजना का भारत पर पड़ने वाले संभावित परिणामों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:

1. भारत पर अपने आसपास के क्षेत्र के अधिकांश अन्य देशों के सापेक्ष योजना का समग्र दुष्प्रभाव अधिक पड़ने वाला है।
2. इस योजना से भारत में खाद्य और वस्त्र जैसे कुछ क्षेत्रों के साथ-साथ दवा उत्पादों को भी जोखिम का सामना करना पड़ सकता है।

उपर्युक्त दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1

(b) केवल 2

(c) 1 और 2 दोनों

(d) उपर्युक्त में से कोई नहीं

Ans. (b)

Q.2. हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर भारत पर उसके ऊंचे टैरिफ को लेकर निशाना साधा और 'परस्पर टैरिफ' लगाने की बात कही है। भारत-अमेरिका के मध्य व्यापार के विभिन्न क्षेत्रों में पारस्परिक टैरिफ के अंतर को लेकर निम्नलिखित कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

(a) ऑटोमोबाइल सेक्टर में टैरिफ अंतर लगभग 23 प्रतिशत है।

(b) रसायन और फार्मास्यूटिकल्स में टैरिफ अंतर लगभग 9 प्रतिशत है।

(c) कृषि क्षेत्र में टैरिफ में अंतर अन्य सभी क्षेत्रों में सर्वाधिक है।

(d) उपर्युक्त सभी कथन सही हैं।

Ans. (d)

Q.3. हाल ही में चर्चा में रहे मिस्र की 'गाजा पुनर्निर्माण योजना' के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:

1. अरब लीग द्वारा 53 अरब डॉलर के अगले पांच वर्षों में गाजा के पुनर्निर्माण करने की इस योजना के प्रस्ताव को स्वीकार किया गया है।

2. हालांकि हमास एवं इजरायल दोनों ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया है।

उपर्युक्त दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं ?

(a) केवल 1

(b) केवल 2

(c) 1 और 2 दोनों

(d) उपर्युक्त में से कोई नहीं

Ans. (a)

+918988885050
+918988886060
www.vajiraoinstitute.com
info@vajiraoinstitute.com

Q.4. हाल में चर्चा में रहे 'केदारनाथ रोपवे परियोजना' के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) यह रोपवे परियोजना सोनप्रयाग से केदारनाथ तक 12.9 किलोमीटर लंबी होगी।

(b) इसे 'डिजाइन, निर्माण, वित्त, संचालन और हस्तांतरण' मोड पर विकसित किया जाएगा।

(c) इससे केदारनाथ मंदिर की वर्तमान यात्रा में एक तरफ लगने वाला समय 8 से 9 घंटे से घटकर केवल 36 मिनट रह जाएगा।

(d) उपर्युक्त सभी कथन सही हैं।

Ans. (d)

Q.5. चर्चा में रहे 'फूलों की घाटी' के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:

1. फूलों की घाटी उत्तराखंड में गढ़वाल हिमालय में स्थित यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है।

2. प्रस्तावित गोविंदघाट-हेमकुंड साहिब जी रोपवे परियोजना से यहां पर भी सुगमता से पहुंचा जा सकेगा।

उपर्युक्त दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1

(b) केवल 2

(c) 1 और 2 दोनों

(d) उपर्युक्त में से कोई नहीं

Ans. (c)